भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2464

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और आईपीएचएल

†2464. श्री नीरज मौर्य:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं एवं शाहजहांपुर जिलों में 'क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स' तथा 'एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं' का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तराई क्षेत्र होने के कारण उक्त जिलों में मलेरिया एवं मेनिन्जाइटिस के बढ़ते मामलों की निगरानी हेतु कोई रियल-टाइम सर्विलांस प्रणाली सक्रिय है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय स्तर पर औषधियों के भंडारण हेतु ब्लॉक-स्तरीय कोल्ड चेन विकसित की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिला अस्पतालों में डायलिसिस एवं कीमोथेरेपी सुविधाओं के विस्तार हेतु आवंटित बजट का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतावराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है। प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 5 वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-2026) के लिए 5249.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 1670 भवन रहित स्वास्थ्य

केंद्रों (एसएचसी-एएएम) का निर्माण, 674 शहरी-एएएम का संचालन, 515 बीपीएचयू की स्थापना, 75 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) का निर्माण/सुदृढ़ीकरण तथा जिला अस्पतालों/ सरकारी मेडिकल कॉलेज स्तर पर 74 गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना शामिल है।

बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में गहन परिचर्या ब्लॉक और एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	जिला	सीसीबी		आईपीएचएल	
		अनुमोदित	स्थिति	अनुमोदित	स्थिति
1.	बरेली	1	भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हो सकी और इसे लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया।	1	भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना शुरू नहीं हो सकी।
2.	बदायूं	1	कार्य शुरू हो गया है। 48% कार्य पूरा हो चुका है।	1	पूर्ण हुआ
3.	शाहजहांपुर	1	कार्य शुरू हो गया है। 50% कार्य पूरा हो चुका है।	1	पूर्ण हुआ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एकीकृत रोग निगरानी मंच (यूडीएसपी) पोर्टल का उपयोग राज्य भर में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एईएस/जेई और अन्य जलजनित रोगों की नियमित निगरानी के लिए किया जाता है। प्रत्येक जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों से दैनिक, उचित समय का डेटा यूडीएसपी पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इस डेटा का विश्लेषण जिला महामारी विज्ञानी/जिला निगरानी इकाई द्वारा दैनिक आधार पर और राज्य स्तर पर राज्य निगरानी इकाई द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत डायलिसिस सेवाओं के विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये आवश्यकताएँ राज्यों द्वारा किए गए डायलिसिस की मांग के आकलन और उनके समग्र संसाधन बजट के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठक में चर्चा की जाती है और मौजूदा मानदंडों

के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के अनुमोदन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई या चल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर आरओपी के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को टीकों के उचित भंडारण और वितरण के लिए आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर (आईएलआर), डीप फ्रीजर (डीएफ), वॉक-इन कूलर (डब्ल्यूआईसी), वॉक-इन फ्रीजर (डब्ल्यूआईएफ), सोलर रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और आइस पैक उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य पीएमएनडीपी की 31 दिसंबर, 2025 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमएनडीपी सभी 75 जिलों में पीपीपी मोड के माध्यम से संचालित है। वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के 67 जिला अस्पतालों के लिए डे केयर सेंटर भी स्वीकृत किए गए हैं।

*****